

भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 1024
25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

दुःसाध्य स्थानिक रोगों का उन्मूलन

†1024. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में, विशेष रूप से बिहार में, सरकार द्वारा शुरू की गई/क्रियान्वित की जा रही प्रमुख स्वास्थ्य परियोजनाओं/विशेष कार्यक्रमों का व्यौरा क्या है;
- (ख) उक्त परियोजनाओं पर संभावित लागत कितनी है तथा इन परियोजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है;
- (ग) क्या सरकार ने किसी ऐसे क्षेत्र की पहचान की है जहाँ उक्त राज्य सहित देश में दुःसाध्य स्थानिकमारी रोगों के उन्मूलन के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों की आवश्यकता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है;
- (घ) उक्त राज्य सहित देश के आकांक्षी जिलों में कार्यान्वित की जा रही उक्त परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा उनका व्यौरा क्या है; और
- (ङ) उक्त परियोजनाओं की आगे की प्रगति के लिए सरकार द्वारा क्या उचित कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके समग्र संसाधन के अंतर्गत, उनके कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) में प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर, जिला अस्पतालों तक उनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करती है। बिहार सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू की गई स्वास्थ्य परियोजनाओं, व्ययगत लागत, दीर्घकालिक स्थानिकमारी रोगों के उन्मूलन हेतु विशिष्ट कार्यक्रम का पूरा विवरण उपलब्ध है और इसे <https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744> लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) का उद्देश्य आकांक्षी जिलों में उप-स्वास्थ्य केंद्र, शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र, ब्लॉक जन स्वास्थ्य इकाइयों के लिए सहायता, एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं (आईपीएचएल) और गहन चिकित्सा इकाईयों (सीसीबी) सहित 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ देश में अवसंरचना विकास सहायता प्रदान करना है। देश में कुल 744 आईपीएचएल और 621 सीसीबी स्वीकृत हैं, जिनमें बिहार में 38 आईपीएचएल और 38 सीसीबी शामिल हैं।

15वें-वित्त आयोग ने राज्यों में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से पाँच वर्षों (2021-2026) की अवधि में कुल 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है। देश में कुल 605 भवन रहित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अनुमोदित हैं, जिनमें बिहार में 103 सीएचसी शामिल हैं।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीबीडीसी) बिहार सहित, उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जहां ये रोग स्थानिकमारी है, में छह वेक्टर जनित रोगों (बीबीडी) - मलेरिया, कालाजार, जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस - की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम नामतः राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनबीबीडीसीपी) का संचालन करता है।

बिहार एक ऐसा राज्य है जहां कालाजार (केए) और लिम्फेटिक फाइलेरियासिस (एलएफ) के लिए स्थानिकमारी है। कालाजार बिहार के 33 जिलों के 485 ब्लॉक में स्थानिकमारी है। सभी 633 कालाजार स्थानिकमारी ब्लॉक ने वर्ष 2023 में उन्मूलन लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिया है।

लिम्फेटिक फाइलेरियासिस देश के 20 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 345 जिलों में स्थानिकमारी है, जिसमें बिहार भी शामिल है। भारत ने हाल के दिनों में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के लक्ष्य की दिशा में प्रगति में तेजी लाने के लिए कई उपाय किए हैं, जिसमें लिम्फेटिक फाइलेरियासिस के उन्मूलन के लिए उन्नत पांच-आयामी कार्यनीति की शुरुआत शामिल है और इनमें से एक महत्वपूर्ण कार्यनीति नामतः पेन इंडिया मास ड्रग एडमिस्ट्रेशन (एमडीए) अभियान मिशन मोड पर है जो वर्ष में दो बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को 159 लिम्फेटिक फाइलेरियासिस प्रभावित स्थानिकमारी जिलों को कवर करता है।

विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, प्रगति और कार्यनिष्पादन का नियमित रूप से समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय दौरों के साथ-साथ राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी), सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम), स्वास्थ्य निगरानी सूचना प्रणाली (एचएमआईएस), प्रजनन बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) पोर्टल, आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) पोर्टल और गैर संचारी रोग (एनसीडी) पोर्टल द्वारा वार्षिक कार्यक्रम योजना और समीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है।
